भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 465

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम में सुधारों का कार्यान्वयन

465. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के वित्तीय प्रबंधन और खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण में प्रचालन की दक्षता में सुधार हेतु उसके पुनर्गठन हेतु शांता कुमार समिति द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने की योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा एफसीआई के कामकाज को सुव्यवस्थित और तीव्र गति से सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे ऐसे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): जी हाँ।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पुनर्गठन पर श्री शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने एफसीआई के प्रशासनिक, कार्यात्मक और वित्तीय ढांचे की व्यापक समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण में एफसीआई के वित्तीय प्रबंधन और परिचालन दक्षता में सुधार करने से संबंधित इसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई **अनुबंध-क** में दी गई है।

(ग): लागू नहीं।

(घ): विवरण **अनुबंध-क** में संलग्न है।

*****

(अनुबंध-क)

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और एफसीआई द्वाराउन पर की गई कार्रवाई

क्र. सं.	सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1.	उच्च स्तरीय समिति सिफारिश करती है कि एफसीआई गेहूं, धान और चावल के सभी खरीद संचालन उन राज्यों को सौंप दे, जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने खरीद के लिए उचित बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पंजाब।	एफसीआई ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा में खरीद संचालन पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंप दिया है। हाल ही में, असम ने केएमएस 2023-24 से दो जिलों, बोंगाईगांव और विश्वनाथ जिलों में चावल की खरीद के लिए डीसीपी पद्धति को अपनाया है। संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर एफसीआई पंजाब और हरियाणा में खरीद संचालन में भाग ले रहा है। एफसीआई ने केंद्रीय पूल के लिए की गई कुल खरीद में से केएमएस 2023-24 और आरएमएस 2025-26 के दौरान क्रमशः लगभग 0.2% धान और लगभग 7% गेहूं खरीदा। शेष खरीद राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा की गई। गेहूं और चावल की खरीद के लिए डीसीपी राज्यों का विवरण निम्नानुसार है:

चावल और गेहूं के लिए डीसीपी राज्य		
क्र.सं.	चावल	गेहूं
1	आंध्र प्रदेश	बिहार
2	बिहार	छत्तीसगढ
3	छत्तीसगढ	गुजरात
4	गुजरात	मध्य प्रदेश
5	कर्नाटक	महाराष्ट्र
6	केरल	पंजाब
7	मध्य प्रदेश	उत्तराखंड
8	महाराष्ट्र	पश्चिम बंगाल
9	ओडिशा	हिमाचल प्रदेश
10	तमिलनाडु	
11	तेलंगाना	
12	त्रिपुरा	
13	उत्तराखंड	
14	पश्चिम बंगाल	
15	हिमाचल प्रदेश	
16	झारखंड	
17	असम (केवल दो जिलों में, अर्थात् बोंगाईगांव और विश्वनाथ)	

2.	एफसीआई इन राज्य सरकारों (गैर-मिलर्स) से केवल अधिशेष (एनएफएसए के तहत राज्यों की	विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) वाले राज्यों के लिए एफसीआई द्वारा केवल अधिशेष खाद्यान्न ही स्वीकार किया जाता है।

	जरूरतों में कटौती के बाद) को घाटे वाले राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए स्वीकार करेगा।	
3.	एफसीआई को उन राज्यों की मदद करनी चाहिए जहां किसान एमएसपी से काफी कम कीमत पर संकटग्रस्त बिक्री से पीड़ित हैं, तथा जहां छोटे जोत वाले किसान अधिक हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि।	पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में एमएसपी संचालन की पहुँच बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों को निरंतर प्रयास और सहायता प्रदान की गई है। केएमएस 2021-22 में, पूर्वी/पूर्वोत्तर राज्यों में 107.31 लाख टन धान (चावल के रूप में) की खरीद की गई, जबकि केएमएस 2020-21 के दौरान 105.77 लाख टन धान (चावल के रूप में) की खरीद की गई थी। केएमएस 2022-23 और केएमएस 2023-24 में पूर्वी राज्यों में क्रमशः 99.36 लाख टन और 76.83 लाख टन धान (चावल के रूप में) की खरीद की गई है। केएमएस 2024-25 के दौरान, 15.07.2025 तक पूर्वी राज्यों में 90.36 लाख टन धान (चावल के रूप में) की खरीद की गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पूर्वी राज्यों में गेहूं की खरीद पर भी जोर दिया गया है। डीएफपीडी, एफसीआई और राज्य सरकारों के पूर्व और जोरदार प्रयासों के कारण पिछले दो विपणन मौसमों की तुलना में आरएमएस 2025-26 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद में वृद्धि हुई है।
4.	खरीद में गुणवत्ता जाँच का पालन करना होगा, और निर्दिष्ट गुणवत्ता से कम गुणवत्ता वाली कोई भी चीज़ केंद्रीय पूल के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं होगी। गुणवत्ता जाँच, एफसीआई और/या किसी तृतीय पक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा,	1. विभिन्न एफसीआई गोदामों में खरीदे और संग्रहीत खाद्यान्नों के यादृच्छिक नमूनों को समय-समय पर गुणवत्ता जांच के लिए एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है। 2. एफसीआई ने खाद्य सुरक्षा संस्थान (आईएफएस) गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है जो आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित है। इसके अलावा, पंचकूला, हैदराबाद, रायपुर और भुवनेश्वर में चार (04) आधुनिक क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें फोर्टिफाइड चावल में फोर्टिफाइड तत्वों के स्तर सहित खाद्यान्नों के रासायनिक मापदंडों के परीक्षण की सुविधाएं हैं।

	गुणवत्ता जाँच की मशीनीकृत प्रक्रियाओं की सहायता से पारदर्शी तरीके से की जा सकती है।	3.एफसीआई ने चावल मिल मालिकों से खरीद के समय पुराने और ताजा मिल्ड कच्चे चावल के बीच अंतर करने के लिए केएमएस 2021-22 से कस्टम मिल्ड कच्चे चावल की आयु निर्धारित करने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से मान्य मिश्रित संकेतक विधि शुरू की है, ताकि सार्वजनिक खरीद में किसी भी पुनर्नवीनीकृत पुराने चावल को देने की मिल मालिकों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। 4. खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और मानवीय व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए प्रमुख चावल खरीद केंद्रों पर 400 एआई आधारित स्वचालित अनाज विश्लेषक स्थापित किए गए हैं। 5. भारतीय खाद्य निगम में डिपो स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक कार्यरत सभी प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) एप्लीकेशन के माध्यम से एकीकृत किया गया है। खरीद के दौरान नमूनों का विश्लेषण, उसके बाद सुपर चेक निरीक्षण और खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए अन्य निरीक्षणों की रिपोर्ट अब क्यूएमएस के माध्यम से दी जा रही है।
5	जब भी स्टॉक बफर स्टॉक मानदंडों से अधिक हो जाए तो ओएमएसएस या निर्यात बाजारों में स्टॉक का परिसमापन करना।	वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए ओएमएसएस (खुला बाजार बिक्री योजना) के अंतर्गत क्रमशः 46.53 लाख टन और 15.41 लाख टन चावल का परिसमापन किया गया है। वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए ओएमएसएस (खुला बाजार बिक्री योजना) के अंतर्गत क्रमशः 40.93 लाख टन और 101.38 लाख टन गेहूँ का परिसमापन किया गया है।
6	एचएलसी ने सिफारिश की है कि एफसीआई को अपने भंडारण कार्यों को विभिन्न एजेंसियों को आउटसोर्स करना चाहिए।	एफसीआई भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएँ सृजित/किराए पर ली जाती हैं। एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूँ के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) संचालन पर निर्भर करती है।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने आवश्यकतानुसार खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। एफसीआई निजी निवेशकों की भागीदारी और निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भंडारण क्षमता में वृद्धि करता है:-
1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
3. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत निर्माण</td></tr>
<tr><td>7</td><td>भारत को अधिक थोक हैंडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता है। अगले 3-5 वर्षों में गेहूं और चावल के लिए कुल मिलाकर लगभग 100 लाख टन क्षमता के साइलो बनाए जाने चाहिए।</td><td>भंडारण सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए, भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत देश भर में साइलो के निर्माण हेतु एक कार्य योजना को मंजूरी दी है।

पूरे हो चुके और उपयोग में लाए जा रहे साइलो इस प्रकार हैं -

<table>
<tr><th>साइलो का मॉडल</th><th>क्षमता (लाख टन)</th></tr>
<tr><td>सर्किट आधारित मॉडल (2007-09)</td><td>5.50</td></tr>
<tr><td>रेलवे साइडिंग और रोड फेड मॉडल</td><td>19.25</td></tr>
<tr><td>हब एवं स्पोक चरण-1(डीबीएफओटी)</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>27.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्माणाधीन साइलो निम्नानुसार हैं -</td></tr>
<tr><td>साइलो का मॉडल</td><td>क्षमता (लाख टन)</td></tr>
<tr><td>रेलवे साइडिंग और रोड फेड मॉडल</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>हब एवं स्पोक चरण-1(डीबीएफओटी)</td><td>7.125</td></tr>
<tr><td>हब एवं स्पोक चरण-1(डीबीफओओ)</td><td>24.75</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>36.875</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>कवर और प्लिन्थ (सीएपी)</td><td>गेहूं खरीद करने वाले राज्यों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में कवर क्षमता सृजित करने के लिए, खुले भंडारण</td></tr>
</table>

	भंडारण को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए और सीएपीमें तीन महीने से ज़्यादा अनाज का कोई भंडार नहीं रहना चाहिए। जहां भी संभव हो, साइलो बैग प्रौद्योगिकी और पारंपरिक भंडारण को सीएपी का स्थान लेना चाहिए।	को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए पंजाब और हरियाणा में नई क्षमता (90 लाख टन) स्वीकृत की गई।
9	उच्च स्तरीय समिति ने एफसीआई द्वारा नियोजित विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के वेतन में भारी असमानता देखी। ऐसा अधिसूचित डिपो में प्रोत्साहन प्रणाली और व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रॉक्सी श्रमिक के कारण होता है। इसका समाधान किया जाना चाहिए, या तो इन डिपो को गैर-अधिसूचित करके, या उन्हें सेवा अनुबंधों पर राज्यों या निजी क्षेत्र को सौंपकर, और प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन की एक अधिकतम सीमा तय करके, जिससे उन्हें	• श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 06.07.2016 की अधिसूचना के तहत सभी 226 डिपो/रेलहेड्स को 2 वर्ष की अवधि के लिए संविदा श्रमिक (आर एंड ए) अधिनियम 1970 की धारा 10 की प्रयोज्यता से छूट दी गई और तब से वे छूट का विस्तार प्रदान कर रहे हैं। • संविदा श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार लाने तथा बेहतर सुविधाएं और ईपीएफ, न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, श्रमिक मुआवजा आदि जैसे पर्याप्त कल्याणकारी प्रावधान तथा कैंटीन/शौचालय, मूत्रालय, पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। • माननीय बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/2014 में दिनांक 20.11.2015 को दिए गए निर्णय के अनुसार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विभागीय श्रमिक संवर्ग को 'मृतप्राय संवर्ग' घोषित किया गया है। • विभागीय सेवा कर्मियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुमोदन से, शुरू में 90 दिनों के लिए शुरू की गई थी। तत्पश्चात, क्षेत्रीय कार्यालयों/श्रमिक संघों के अनुरोध पर इसेदिनांक20.01.2025 तक बढ़ा दिया गया।दिनांक20.01.2025 तक, कुल 1,212 विभागीय

	उनके साथ सहमत कार्य के लगभग 1.25 गुना से अधिक काम करने की अनुमति न मिले। इन डिपो को मशीनीकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि विभागीय श्रमिकों पर निर्भरता कम हो। यदि आवश्यक हो, तो एफसीआई को डीपीएस/एनडब्ल्यूएनपी प्रणाली के तहत लोगों को नियुक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एचएलसी ने सिफारिश की है कि संविदा श्रमिकों, जो सबसे अधिक मेहनत करते हैं और जिनकी संख्या सबसे अधिक है, को बेहतर सुविधाएँ देकर उनकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।	श्रमिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का विकल्प चुना।
10.	उच्च स्तरीय समिति ने किसानों से खरीद से लेकर भंडारण, परिवहन और अंततः लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	अन्न दर्पण परियोजना शांता कुमार समिति द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन है। एफसीआई की **अन्न दर्पण परियोजना**, जो वर्तमान में विकासाधीन है, शांता कुमार समिति (2015) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसने संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली - खाद्यान्नों की खरीद से लेकर उनके भंडारण, आवाजाही और

	(टीपीडीएस) के माध्यम से वितरण तक, संपूर्ण खाद्य प्रबंधन प्रणाली के पूर्णतः कंप्यूटरीकरण की सिफारिश की है। यह वास्तविक समय के आधार पर किया जा सकता है, और कुछ राज्यों ने खरीद कार्यों के कंप्यूटरीकरण में सराहनीय कार्य किया है। लेकिन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में परिवहन और वितरण के साथ इसका तालमेल एक कमज़ोर कड़ी रहा है, और यहीं पर ज़्यादातर विचलन होता है।	नामित एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को अंतिम रूप से जारी करने के शुरू से अंत तक के डिजिटलीकरण की पुरज़ोर सिफ़ारिश की थी। इस परियोजना को एक केंद्रीकृत, एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो खरीद, भंडारण, आवाजाही, बिक्री, अनुबंध और सूची प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और श्रमिक जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करेगा। लागू होने के बाद, यह वास्तविक समय की निगरानी, राज्य खरीद पोर्टलों के साथ एकीकरण को सक्षम करेगा और डिजिटल वर्कफ़्लो और ऑडिट ट्रेल्स के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा। इस प्रकार, अन्न दर्पण समिति की सिफारिशों के अनुरूप एफसीआई के संचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। **1.डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस)**: खरीद, भंडारण और संचलन प्रचालन के कम्प्यूटरीकरण/स्वचालन के लक्ष्य के साथ डिपो ऑनलाइन प्रणाली दिनांक 01.12.2018 को शुरू की गई थी और वर्तमान में यह सभी एफसीआई डिपो के साथ-साथ किराए के डिपो में भी कार्यशील है। **2. विंग्स:** चावल मिलों को डिपो से जोड़ने और डिपो में स्टैक स्पेस के आबंटन को स्वचालित करने के लिए, भारतीय खाद्य निगम ने वेयरहाउस इन्वेंटरी नेटवर्क एवं गवर्निंग सिस्टम (विंग्स) विकसित किया है। इस प्रणाली द्वारा तैयार की गई स्वचालित लिंकेज योजनाएँ मिल मालिकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देती हैं। यह स्वचालित प्रणाली मिल मालिकों को डिपो में स्टैक स्पेस बुक करने और डिपो स्पेस के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है। यह प्रणाली अब केएमएस 2023-24 से सभी चावल खरीद क्षेत्रों में पूरी तरह से चालू हो गई है। **3.** एनआईसी और एफसीआई द्वारा 2022 में शुरू किए गए **केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी)** का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) स्टॉक के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच तैयार करना है। सीएफएसपी खाद्यान्न भंडारण में दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाता है, बेहतर निर्णय लेने और राष्ट्रीय खाद्य भंडार के मज़बूत प्रबंधन में सहायता करता है।

		4. केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी): भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने एक ऐसे एप्लिकेशन इकोसिस्टम की परिकल्पना की है, जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाने वाली एमएसपी खरीद, निगरानी और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए, सभी राज्य खरीद पोर्टलों को समान मापदंडों के साथ एकीकृत करके, एक ही स्रोत पर उपलब्ध हो। खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2021-22 से संपूर्ण खरीद कार्यों का डिजिटलीकरण लागू कर दिया गया है। **5. वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) :** खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की देखरेख में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सड़क परिवहन ठेकेदारों (आरटीसी) का उपयोग करके प्रेषण डिपो से प्राप्त डिपो तक खाद्यान्नों के परिवहन के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इस संबंध में, जीपीएस सक्षम लाइव ट्रैकिंग समाधान अर्थात वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) विकसित की गई है, ताकि पारगमन (रेल के साथ-साथ सड़क) में खाद्यान्नों की ई-निगरानी की जा सके और रास्ते में खाद्यान्नों की चोरी की संभावनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की शुरू से अंत तक की आवाजाही की लाइव ट्रैकिंग के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग प्रणाली (वीएलटीएस) को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। दिनांक 04.07.2025 तक कुल 304 ट्रांसपोर्टरों को शामिल किया गया है और कुल 105301 यात्राएं पूरी की गई हैं।

******